रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बृहस्पतिवार, 20 अप्रैल, 1989/30 चैत्र, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-4, the 10th April, 1989

No. 1-14/89-VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, the Himachal Pradesh

Town and Country Planning (Amendment) Bill, 1989 (Bill No. 7 of 1989) having been introduced on the 10th April, 1989, in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is published in the Gazette.

LAXMAN SINGH,
Secretary.

1989 का विधेयक संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 1989

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 1989 है ।

धारा 67 का संशोधन

1977 का 12

2. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 67 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा (2) रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(2) The Chairman shall receive such salary and allowances and shall be subject to such terms and conditions as may be determined by the State Government.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 67 में, उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन गठित विशेष क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने का उपबन्ध है । कतिपय क्षेत्रों, विशेषतः पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में, पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी को ऐसे प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना सम्भव नहीं होता है । उन क्षेत्रों में ऐसे प्राधिकरणों के कृत्यों का उस क्षेत्र में नियुक्त, राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों द्वारा, अपने कृत्यों के साथ-साथ, अधिक सुविधापूर्वक और प्रभावशाली रूप से निर्वहन किया जा सकता है । इसलिए कथित धारा का संशोधन करना आवश्यक समझा गया है ताकि परिस्थितियों के अनुसार पूर्णकालिक वैतनिक से भिन्न अधिकारियों को विशेष क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सके ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

शिमला :
10 अप्रैल, 1989.

वीरभद्र सिंह,
प्रभारी मन्त्री ।

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधिनियमित किए जाने से राजकोष पर कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं पड़ेगा ।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

शून्य

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Nagar Aur Gram Yojna (Sanshodhan) Vidheyak*, 1989 (1989 *ka Vidheyak Sankhyank* 7) *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Bill No. 7 of 1989.

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL, 1989

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (*Act No.* 12 *of* 1977).

BE it enacted by the Himachal Pradesh Legislative Assembly in the Fortieth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 1989. Short title.

2. For sub-section (2) of section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, the following sub-section (2) shall be substituted, namely:— Amendment of section 67.

12 of 1977

"(2) The Chairman shall receive such salary and allowances and shall be subject to such terms and conditions as may be determined by the State Government".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 provides for appointment of whole time salaried officer as Chairman of Special Area Development Authorities to be constituted under section 66 of the said Act. In certain areas, especially in rural and tribal areas, it is not feasible to appoint whole time salaried officer as Chairman of such authorities. In those areas functions of such authorities can more conveniently and effectively be performed by the officers of the State Government posted there in addition to their own duties. It has, therefore, been considered necessary to amend the said section so that the officers other than the whole time salaried officers may, wherever circumstances so warrant, also be appointed as Chairman of Special Area Development Authorities.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

VIRBHADRA SINGH,
Minister-in-charge.

SHIMLA:
The 10th April, 1989.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions contained in the Bill, when enacted, will not cause any additional expenditure out of the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।